

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजरख विभाग

देहरादून: दिनांक 23 जुलाई, 2008

विषय:- मै0 एन0टी0पी0सी0 जल विद्युत आवासीय सहकारी समिति को कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलौनी के निर्माण हेतु जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम पौन्धा में कुल 5.50 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1146/12ए-137(2005-06)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 29 मार्च 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय मै0 एन0टी0पी0सी0 जल विद्युत आवासीय सहकारी समिति को कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलौनी के निर्माण हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 (2) एवं उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(अ) के अन्तर्गत जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम पौन्धा में जिलाधिकारी के उपरोक्त पत्र दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं की कुल 5.50 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया

जायेगा, उसी प्रयोजन (सहकारी समिति के कर्मचारियों के लिए आवासीय कालौनी के निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गयी भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन की अवधि के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

7- संस्था आवास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था से ही निर्माण कार्य करायेगी, तथा क्लस्टर, नेवरहुड एवं टाउनशिप विकास हेतु मार्गनिर्देशिका से समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

8- संस्था मात्र अपनी पंजीकृत समिति के सदस्यों को ही आवासीय सुविधा उपलब्ध करायेगी और समिति के इतर अन्य व्यक्तियों को भूमि आदि विक्रय नहीं करेगी।

9- प्रश्नगत क्षेत्र में आवास विभाग द्वारा प्रचलित भवन उपविधियों/विनियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के उपरान्त आवास विभाग के शासनादेशों के क्रम में प्रोजेक्ट/मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पृथक से आवास विभाग/उत्तराखण्ड शासन के समक्ष आवेदन किया जायेगा।

11- किसी भी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा ना हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जायेगा।

12- अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त भूमि का अन्तरण/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी स्थिति में विक्रय की दशा के कारणों का उल्लेख करते हुए शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

13- आवासीय कालौनी के स्थापना से पूर्व सभी वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां/अनुज्ञाएँ/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- श्री राजीव चोपड़ा, महासचिव, एन0टी0पी0सी0 जल विद्युत आवासीय स्वायत्त सहकारिता, 233- ले0न0- 9, मोहित नगर, देहरादून।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सन्तोष खड़ोनी)
अनुसचिव।